THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under discussion and no decision has been taken.

Onge Tribe

1473. SHRI S. S. SOMANI:

SHRI DINEN BHATTACHARYA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of Onge tribe has been progressively dwindling from 672 at the turn of this century and they are now only 100 in the little Andaman Island;

(b) whether it is a fact that it is due to certain varieties of the plant found like Tuber which contain small quantities of diosgenin and are edible and due to its heavy dependence for food on tubers of a plant called dioscoreas; and

(c) if so, whether Government have made any efforts in this regard and studied the facts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) The population of Onges was assessed at 672 in 1901. It stood at 129 according to the 1961 census and 112 according to the census of 1971.

(b) and (c). Investigations seem to indicate that the diosgenin in the dioscorea plant is unlikely to be the cause of sterility among the Onges. A doctor has now been posted at Dugong Creek to attend exclusively to the Onges in the area. Higher technical support is being provided in health matters by the Jawaharlal Nehru Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry where a research cell has been established for this purpose.

पश्चिम घाट विकास योजना

1474. श्री एस० एच० बावकः क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम घाट विकास योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) कौन-कौन से राज्य इस योजना में अन्तर्भूत हैं; और

(ग) क्या इस योजना को क्रियान्वित किया गया है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) पश्चिम घाट विकास स्कीम का उद्देश्य इस प्रदेश के निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करना है जिसके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ की गई स्कीम इस प्रकार बनाई गई हैं कि उनसे स्थानीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके स्थानीय लोगों के परिवारों को उनके लिए रोजगार और उनकी आय को बढ़ाकर प्रत्यक्ष लाभ पहुंचे। इन कार्यक्रमों में ये सम्मिलित हैं—भूमि और नमी के संरक्षण तथा भूमि प्रबंध पद्धतियों के साथ फसल सुधार और बगान फसलों के लिए गहन कृषि स्कीमें, पशुपालन, डेरी विकास, बागबानी का विकास और वनोद्योग कार्यक्रम, लघु उद्योगों का विकास और पर्यटन विकास। पांचवीं योजना (1974–78) की अवधि में, इन स्कीमों के लिए 13.40 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। 1978–79 के लिए 7.26 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र राज्यों और गोवा संघ शासित क्षेत्र के निर्धारित क्षेत्र आते हैं।

(ग) ये विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।